होता है तो उसको देखते हुए क्या सरकार ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे भविष्य में जीवन पर कोई खतरा न उपस्थित हो या नी कोई ऐसी कार्यवाही करेगी जिससे लोगों के जीवन को खतरा न रहे ? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या आप उनको वहां से हटाने के लिए कदम उठाएंगे ?

श्री टी० अंजैय्या : हमने तो कदम उठाया है। लोगों को एरेस्ट किया गया है और फैक्ट्री को बंद किया गया है और सब कुछ किया गया है... (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : हमारा यह कहना है कि लोगों के मरने से पहले क्या आप इस तरह की कार्यवाही करेंगे ? यह तो आपने लोगों के मरने के बाद कार्यवाही की है। आप लोगों के मरने के बाद कार्यवाही करते हैं... (व्यवधान) यह तो मरी हुई सरकार का जवाब है... (व्यवधान)

श्री टी० अंजैय्या : भोपाल के बाद इस मामले पर गवर्नमेंट बहुत सीरीयसली सोच रही है। तमाम फैक्ट्रीज से रिपोर्ट मंगा रहे है और उसके ऊपर जो कुछ भी हो सकता है वह करेंगे। जो आफिसर्स आर्डर्स को इम्पलीमेंट नहीं करेंगे उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हम चीफ इंस्पैक्टर्स की मीटिंग बुला रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि स्टेट्स में उनकी जिम्मेदारी है। वे मैनेजमेंट को एडवाइज करें। क्लोरीन के बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है। स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वे किसी फैक्ट्री को क्लोज कर दें, सिफ्ट कर दें। उनको इन बातों का पूरा अधिकार है। हम कहेंगे तो कहा जाएगा कि किसी के दिमाग की उपज है। फैक्ट्री को क्लोज करने की जिम्मेदारी उनकी है। हमारे ऊपर भी थोड़ी जिम्मेदारी है। हम रिपोर्ट मंगाने के बाद कह सकते हैं।

MR. CHAIRMAN: Question No. 304—Shri Gurudas Das Gupta.

*304. [*The Questioner (Shri Gurudas Das Gupta) was absent. For answer.* vide col. 37-38 infra.]

MR. CHAIRMAN: Question No. 305—Shri Chaturanan Mishra.

Creation of Credit and Collection Division by the ITDC

*305. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in order to realise its huge outstanding arrears ITDC created an independent cell called 'Credit and Collection Division' sometime back;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what amount has been realised by this Division till September, 1985; and

(d) what are the details of the amount outstanding till September, 1985 and what efforts are being made to get the same realised before the end of the current financial year?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND TOURISM (SHRI H.K.L. BHAGAT): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Credit & Collection Division was set up in July 1981 to perform the following broad functions :—

To scrutinise and assist the units in effecting recoveries of outstandings, and to initiate legal action wherever necessary.

The Division was manned by 4 officers and a complement of 8 staff and was headed by the Senior Vice-President (Finance). The staff of the Division was distributed among the concerned units in February, 1985.

(c) Since the Division was primarily created to effect and assist the units in the recovery of outstandings, no parallel records were maintained at Headquarters as it would have duplicated the accounting process. The

records regarding the recovery of outstandings continued to be maintained by the respective units themselves.

(d) The estimated breakup of the amounts outstanding party-wise as on 30 Sep. 85 is as under:—

(Rs. in lakhs)

Government Departments .	574·44
Travel Agents . . .	197·57
Private Parties . . .	66·24
Licensees	82·05
Credit Card holders . .	38·21
Others	78·08
TOTAL .	1036·59

The process of debt collection is continuous in the ITDC due to its nature of business. To accelerate the process of recovery of outstandings, following steps are being taken:—

—supplementing the strength of the units by deploying additional staff wherever necessary.

—seeking the assistance of the Government for realising the outstandings against Government Departments/Ministries, etc.

—steps to computarise the accounts.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, राजकीय क्षेत्र की जो बीमारी है, वह आई० टी० डी० सी० के संबंध में जो ब्यान दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है उससे स्पष्ट होता है। दस करोड़ का बकाया है उसमें से पांच करोड़ से कुछ अधिक राशि सरकारी क्षेत्र की बकाया है और पांच करोड़ के लगभग प्राइवेट सेक्टर की बाकी है। मैं समझता हूं कि राजकीय क्षेत्र के विकास के लिए यह सबसे बड़ी बाधा है। मंत्री महोदय के जवाब से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह बकाया राशि कब से और किस के यहां बकाया है।

इसलिए मैं पहली बात यह जानना चाहूंगा कि जो बकाया है वह कब से बाकी है और किन-किन प्राइवेट एजेन्ट्स के यहां बाकी है, प्राइवेट प्रापरटीज में किस-किस के यहां बाकी है और डेड लोन कह करके पिछले चार वर्षों के अंदर जब से यह कमेटी बनी है किन-किन को माफ कर दिया गया है। मुझे रिपोर्ट है यह कुछ लोगों का चरागाह बन गया है जिसमें राजनीतिज्ञ भी हैं। इसलिए मैं इन चार बिन्दुओं पर मंत्री महोदय से जवाब चाहता हूं?

श्री एच० के० एल० भगत : सर पहला प्रश्न जो आनरेबल सदस्य ने पूछा है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और दूसरे लोग पैसा नहीं देते हैं यह एक अच्छी चीज नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पैसा जल्दी वापस करना चाहिए और इस मंत्रालय के सेक्रेटरी ने अभी कुछ अर्से पहले सभी को लिखा है कि पैसा दें। कुछ पैसा मिला भी है। मैं भी अपने लेबल पर सभी मिनिस्टर्स कन्सर्न या अंडरटेकिंग्स हैड्स को लिख रहा हूं कि पैसा जल्दी से वापस देना चाहिए। दूसरा, एक-एक नाम मेरे पास नहीं है लेकिन मोटे तौर पर कुछ तीन महीने से, कुछ 6 महीने से, कुछ एक साल से, कुछ दो साल से और कुछ तीन साल से भी हैं। यह सारी तफसील मेरे पास है और अगर आनरेबुल सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। मोटे तौर पर होटल के पेमेंट है या ट्रेवल के पेमेंट हैं। यहां क्रेडिट का सिस्टम होता है। सब जगह दुनियां में क्रेडिट सिस्टम है। जहां तक किसी को माफ करने का सवाल है इसके बारे में अभी तक मेरे ज्ञान में कोई बात नहीं है। आनरेबुल सदस्य को पता हो, इन्फार्मेशन हो, यहां पर जनरल वे में उन्होंने कहा, लेकिन अगर वे स्पेसिफिक मामला दें तो मैं इस बात का एश्योरेंस देना चाहता

हूं कि किसी को भी माफ करने का और पोलिटिशियन इसमें हैं, ऐसी कोई चीज मेरे नोटिस में नहीं है और किसी का कोई लिहाज इस सिलसिले में बरतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो गवर्नमेंट का रुपया है वह रुपया वापस लिया जायेगा। जहां एक तरफ कर्जे हैं जो कि लेने हैं वहां दूसरी तरफ आई० टी० डी० सी० का टर्न-ओवर काफी बढ़ा है और ज्यादा बढ़ रहा है।

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि एक साल से भी ज्यादा से बकाया पड़ी हुई हैं। वे अभी नाम तो नहीं दे सके और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके नोटिस में नहीं है। उन्होंने यह जो कहा कि नोटिस में नहीं आया तो यही तो हमारी शिकायत है कि सरकार की नोटिस में आए बिना ही सारा माल गबन हो जाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि क्या वे कोई इन्क्वायरी कमेटी सेट-अप करेंगे जिससे ये जो नाजायज ढंग से बातें हुई हैं उसके सम्बन्ध में जांच करके मंत्री महोदय के नोटिस में वास्तविकता को ला सकें?

श्री एच० के० एल० भगत : सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि माल सारा गबन हो जाता है।

That is too wide a statement, which, with due respects to the hon. Member, is not corred.

मैं इस के लिये कोई इन्क्वायरी कमेटी सेट-अप करने की कोई जरुरत नहीं समझता। अगर कोई स्पेसिफिक केस मेरे नोटिस में लाया जायेगा कि किसी के ऊपर नाजायज पैसा छोड़ दिया गया है तो मैं उसे देखूंगा और वह पैसा जो आउट स्टेंडिंग हैं उसको क्लेक्ट करने के लिये विगरस एफर्टस की जायगी। इस तरह का जो भी पैसा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के पास या उच्च अन्य किसी प्राइवेट कन्सर्न के पास होगा, इसके लिये विगरस एफर्ट्स की जायेंगी कि पैसा गवर्नमेंट को वापस मिले।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Sir, the Minister's answer is self-contradictory. He has said that this unit, this division, credit and collection division, has been formed to scrutinise and assist the individual in the collection of the arrears. But again he says that the staff have been distributed among the individual units. The individual units have already got the staff for the collection purposes. Then, what is the necessity for creating a division and again distributing those people among the individual units? Is that division working in a centralised manner, monitoring these arrears and collections or whether it has been disbanded? Then why this unit could not collect these arrears even from the Government departments?

SHRI H.K.L. BHAGAT: Sir, as far as the first question is concerned, there is no contradiction in the statement whatsoever, nor this division was created. A certain number of officers and staff were put in this division. Then they were distributed so that they can go and assist the various units. It is a question of creating a division and then utilising those different people in those units. There is no question of any contradiction. The second point is that the division has not been disbanded. The division continues but the work in these various components has been distributed to various units. Then, the hon. Member asks why the money has not been collected from the Government departments. It is not correct to say that money has not been collected. Quite a lot of money has been collected and for the remaining amount we are trying our best to collect it and I hope the other Government Department will pay it.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Sir, the answer is not complete. If the Division is continuing, why are they not maintaining records of collection. What is the difficulty.

SHRI H.K.L. BHAGAT: That will mean total duplication These people go there, supervise their accounts and help them to make collections. There

is no point in creating a separate division because that would mean duplication in the work which would be inconvenient and unnecessary.

SHRI V. NARAYANASWAMY: As per the statement of the hon. Minister, the Credit and Collection Division was set up in July, 1981. I want to know whether this Division recommended legal proceedings against the persons about which the hon. Minister has mentioned. How many cases have been taken up for recovery. The hon. Minister has stated that Rs. 78.08 lakhs are due from 'others'. I want to know whether they are VIPs or private companies or corporations. The hon. Minister may clarify.

SHRI H.K.L. BHAGAT: The hon. Member asked whether they are private companies or individuals. As I said, I have got only the broad categorisation with me and not the details of every individual. About legal action, the information is not with me. The hon. Member asked in a general way and I shall enquire about it and if legal action is necessary, it would be taken.

SHRI V. GOPALSAMY: Sir, Minister's answer to part (c) of the main question is evasive. The question was: How much money has been realised. If complete information is not available, and there is no need to keep parallel records, because the Minister said that it will mean duplication of work, then for what purpose have you created this Division?

MR. CHAIRMAN: He has answered that.

SHRI V. GOPALSAMY: I want to know from the hon. Minister whether any accountability or responsibility has been fixed on those executives who allow these credits and then have written off crores of rupees in the name of bad debts.

SHRI H. K. L. BHAGAT: As I have already stated, responsibility lies on different functionaries working in this Division; they are certainly accountable. The hon. Member is assuming as if crores have been written off. I do not have that information whether crores have been written off. He has only given this general information. If he points out any specific case, I will take action.

SHRI JAGESH DESAI: Even in the business organisations, there is a custom that if the amount is not paid within one month or 15 days, interest is charged. Even in case of income-tax payment, if the advance tax payable is not paid within the specified time limit, interest is charged. Same is the position for sales-tax where 24 per cent interest is charged if it is not paid within one month, and the idea is that the assessees should pay the tax in time. I want to know whether interest is charged in this case also if the dues are not paid within a particular time. If interest is charged, what is the rate?

SHRI H.K.L. BHAGAT: I am not aware whether interest is charged or not.

SHRI JAGESH DESAI: How will you recover the money in that case?

SHRI H.K.L. BHAGAT: Shall I say any untruth? I only said that I am not aware whether interest is charger or not. Then so many payments are from Government to Government; from one Ministry to another; from one department to another department, and I shall check up whether provision for interest exists elsewhere or not.

MR. CHAIRMAN: Next question.

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के खेतड़ी समूह में क्षमता का उपयोग

*306. श्री अश्विनी कुमार :†
श्री श्रीधर वासुदेव धाबे :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने अपने खेतड़ी समूह

†सभा में यह प्रश्न श्री अश्विनी कुमार द्वारा पूछा गया ।